Business Standard- 21- November-2022

STORY IN NUMBERS

Tapping into change

The Jal Jeevan Mission, launched in August 2019, aims to provide safe and adequate drinking water through individual tap connections to all households in rural India by 2024.

Only 17 per cent of rural households had tap water connections on August 15, 2019, the Ministry of Jal Shakti informed Parliament on July 28 this year.

Uttar Pradesh (UP), which has been a laggard, has, however, performed better in recent days. The government covered 465,000 rural households (1.76 per cent) with tap water connections in 2019–20 and another 1.91 million households (7.24 per cent) in 2020–21. In the year of the second Covid-19 wave, coverage fell, with just 658,000 households (2.48 per cent) receiving tap water connections in 2021–22.

UP's performance has improved in the current financial year (2022–23), with 1.63 million households covered (6.18 per cent) — and five months to go.

But it has to catch up.

None of the 75 districts had covered more than 50 per cent of the households with tap water supply. In 54 of the 75 districts, less than 25 per cent of households had tap water supply.

The lowest coverage is in Ayodhya district (6.73 per cent) and the highest in Baghpat (49.88 per cent). Six of the top 10 districts by tap water coverage are within the National Capital Region and therefore, beneficiaries of interstate regional planning and development in India's largest urban agglomeration.

TOP FIVE BEST AND WORST PERFORMERS: TAP WATER

The best

Households getting 100% of tap water

- GOA
- TELANGANA
- ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS
- PUDUCHERRY
- DADRA AND NAGAR HAVELI, DAMAN AND DIU

The worst

% of households getting tap water

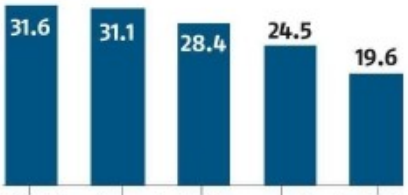

Source: Jal Jeevan Mission dashboard, as on November 1, 2022

Text: ADITI PHADNIS

Sources: IndiaSpend, Jal Jeevan Mission

Hindustan- 21- November-2022

ताकि हर घर नल से चौबीसों घंटे मिल पाए स्वच्छ जल

नितिन बस्सी | प्रोग्राम लीड, सीईईडब्ल्यू

भारत ने हाल ही में 54 प्रतिशत, यानी लगभग 10.4 करोड़ ग्रामीण परिवारों, घरों या परिसरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने का प्रमुख पड़ाव हासिल किया है। यह उपलब्धि बड़ी है, क्योंकि 2019 में सिर्फ 17 प्रतिशत परिवारों के पास ही नल कनेक्शन था। इतना ही नहीं, आठ राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में 100 प्रतिशत ग्रामीण घरों तक नल कनेक्शन पहुंच चुका है। इसका श्रेय केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन (जेजेएम) को जाता है, जिसके तहत सभी ग्रामीण परिवारों को 2024 तक नल कनेक्शन से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस मिशन की विश्व स्तर पर प्रशंसा हो रही है।

हालांकि, नल कनेक्शन से आगे बढ़कर जलापूर्ति की विश्वसनीयता और सुरक्षा (हानिकारक तत्वों व संक्रमणों से मुक्त) बढ़ाने पर अब ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए आवश्यक है कि जल के साथ गुणवत्तापूर्ण आंकड़े भी सुनिश्चित हों, ताकि जहां भी कमियां आएं, उनको दूर किया जा सके।

अभी ग्रामीण जलापूर्ति की निगरानी के लिए दशकीय जनगणना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस), राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) और जेजेएम की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) डैशबोर्ड जैसे विभिन्न स्रोतों के आंकड़ों का इस्तेमाल होता है। हालांकि, कौंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट ऐंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) ने अध्ययन में पाया है कि ग्रामीण पेयजल सेवाओं में प्रगति के आकलन के लिए विभिन्न राष्ट्रीय एजेंसियां जिन संकेतकों का इस्तेमाल करती हैं, वे पानी की विश्वसनीयता और सुरक्षा निर्धारित करने वाले जरूरी संकेतकों से नाममात्र ही मेल खाते हैं। अतः ग्रामीण भारत में पेयजल सेवाओं को सुधारने के लिए पर्याप्त आंकड़ों की जरूरत है। इस दिशा में ये पांच कदम उठाए जा सकते हैं।

जल गुणवत्ता सूचकांक बनाना चाहिए। गांवों में घर-घर तक जल पहुंचा देना ही पर्याप्त नहीं है, गुणवत्ता सुनिश्चित करना जरूरी है।

पहला, मौजूदा सर्वेक्षणों की शब्दावलियों व संकेतकों के लिए मानक बनाया जाना चाहिए। अलग-अलग सर्वेक्षणों से जल के बारे में अलग-अलग सूचनाएं मिलती हैं। ऐसे में, जलापूर्ति में प्रगति के बेहतर आकलन के लिए जरूरी है कि विभिन्न सर्वेक्षण एजेंसियों के बीच संकेतकों और शब्दालियों पर आम सहमति बनाई जाए।

दूसरा, भविष्य के सर्वेक्षणों की सीमाओं को बढ़ाया जाए, ताकि इनमें सुरक्षित पेयजल सेवाओं से जुड़े संकेतकों, जैसे- जलापूर्ति की दर, अवधि, मात्रा और गुणवत्ता को शामिल किया जा सके। उल्लेखनीय है कि जेजेएम में किसी तीसरे पक्ष या एजेंसी से जिले में नल कनेक्शन का वार्षिक मूल्यांकन कराने का प्रावधान मौजूद है। यह नियम इन आकलनों में विभिन्न राष्ट्रीय सर्वेक्षण एजेंसियों को सहयोग करने और उपलब्ध संसाधनों के कुशलतापूर्ण उपयोग का अवसर देता है।

तीसरा, इंटरनेट आधारित स्मार्ट जलापूर्ति निगरानी व्यवस्था को हर गांव तक विस्तार दिया जाए। अभी इसे 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 69 गांवों में प्रायोगिक तौर पर जांचा जा रहा है। यह व्यवस्था मुख्य रूप से प्रति व्यक्ति औसत दैनिक जलापूर्ति की जानकारी देती है। हालांकि, इसे सभी गांवों तक बढ़ाने के लिए सुव्यवस्थित योजना व पर्याप्त निवेश की जरूरत पड़ेगी। इसलिए, इसको चरणबद्ध तरीके से उन क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ लागू किया जा सकता है, जहां जलापूर्ति बढ़ाने में पानी की किल्लत देखी जा रही है।

चौथा, हर नल कनेक्शन के साथ मीटर भी लगाना चाहिए। अभी केवल गांव में हो रही कुल आपूर्ति का ही पता चलता है। किसी गांव में किसी घर में कितनी आपूर्ति हो रही है, इसका पता नहीं चलता। साथ ही, मीटर लगाकर जल के दुरुपयोग को भी रोका जा सकता है। जल की गुणवत्ता की जांच से ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को भी जोड़ना चाहिए।

पांचवां, जल गुणवत्ता सूचकांक बनाना चाहिए, क्योंकि पानी की गुणवत्ता इसके कनेक्शन जितनी ही महत्वपूर्ण है। घर-घर तक जल पहुंचाना ही काफी नहीं है, गुणवत्ता सुनिश्चित करना जरूरी है। अभी महाराष्ट्र जैसे कुछ ही राज्य नदियों और भूजल के वर्गीकरण के लिए जल गुणवत्ता सूचकांक का उपयोग करते हैं। जाहिर है, इन सुझावों को लागू करने से भारत को नल से जल की विश्वसनीयता दिखाने में मदद मिलेगी।

(साथ में कार्तिक गणेशन)